Language for communication between one State and another State and between a State and the Union:

Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

According to Section 3(1) of the Official Languages Act, 1963, the English language may, as from the appointed day, continue to be used, in addition to Hindi, for all the official puposes of the Union for which it was being used immediately before that day and for the transaction of business in Parliament. The Section also provides that the English language shall be used for purposes of communication between the Union and a State which has not adopted Hindi as its official language. further, where Hindi is used for purposes of communication between one State which has adopted Hindi as its official language and another State which has not adopted Hindi as its official language such communication in Hindi shall be accompanied by a translation of the same in the English language.

Besides the four South Indian non-Hindi speaking States, there are non-Hindi speaking States in the East, North-East, West and North India who have adopted their own official languages. Hence the use of Hindi, which is their official language, by the Hindi speaking States cannot be construed as a step likely to cause North-South divide. In view of the above, there is no question of any steps being taken by the Central Government in this regard.

देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी गई सुविधाएं

3327. **कुमारी सईदा खातून :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या कितनी है और उन्हें दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार गांवों में रहने वाले ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण करने का विचार रखती है, जिन्हें अभी तक कोई पेन्शन नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या कितनी है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा उनको दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सूचना गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, 31 जुलाई, 1990 तक केन्द्रीय राजस्व से 1,5 ,0.5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन की मंजूरी दी गई है। पेंशन के अलावा, वे जीवन-भर अपने लिए और पति या पत्नी/सहयोगी के लिए मुफ्त रेलवे पास और सभी केन्द्रीय सहकारी अस्पतालों (केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा संचालित अस्पतालों में) मुफ्त चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के हकदार हैं। कुछ शर्तों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता में उन्हें दिल्ली में सरकारी आवास भी प्रदान किया जाता है। दिल्ली में, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घर भी है, जिनके पास देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Influx of students to India from Myanmar

3328. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to post election developments many youths and students have fled from Burma (Mayanmar) to India to escape from army wrath;